have not been allowed to cross the Efficiency Bar during the last five years ?

(c) whether it is a fact that the Ramjas Society has not taken any action on the directions given by the Directorate of Education Delhi, in the matter; and

(d) if so, what further action is proposed to be taken by the Directorate in this connection ?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA) : (a) and (b) Only five such cases have come to the Education Directorate's notice. The period ranges from 1958 to 1962.

(c) No, Sir. The Ramjas Society is implementing instructions on the subject issued by the Education Directorate.

(b) Does not arise.

शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार

*851. **श्री रघुनाथ प्रसाद खेतान:** क्या; शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में उन्होंने अपने मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये सुधार क्या हैं?

t [ADMINISTRATIVE REFORMS IN THE MINISTRY OF EDUCATION

*851. SHRI R. P. KHAITAN: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state;

(a) whether it is a fact that recently he has carried out administrative reforms in his Ministry; and

(b) if so, What are these reforms ?]

शिक्षा मंत्री (श्री एम० सी० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) मांगी गयी सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

†[ ] English translation.

विवरण

शिक्षा मंत्रालय के कार्य को जल्दी निपटाने के लिये और खर्चे में कमी करने के लिये निम्नलिखित उपाय अपनाये गए हैं:—

(क) 4 मितव्ययता

(i) यह निर्णय किया गया है कि 30 अक्टूबर, 1966 को समाप्त होने वाले पद की मौजूदा मंजूरी के खत्म होने पर शिक्षा मंत्रालय में सचिव के दो पदों में से एक को जारी न रखा जाए। 16 अगस्त, 1966 से वर्तमान पदग्राही के छुट्टी जाने के बाद स्थान को नहीं भरा गया है।

(ii) मंत्री के सचिव का पद, जो उप-सचिव की हैसियत का था, 16 अगस्त, 1966 से समाप्त कर दिया गया है।

(iii) यह निर्णय किया गया है कि शिक्षा मंत्री की विशेष स्वीकृति के बिना कोई नया प्रशासनिक पद नहीं बनाया जाना चाहिये और न भरा जाना चाहिए और नये वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों के बनाने में कठोर नियंत्रण का पालन किया जाना चाहिए।

(iv) हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि समिति आदि की बैठकों में उपस्थिति होने वाले पदाधिकारियों की संख्या कम से कम की जानी चाहिए और जहां तक सम्भव हो केवल एक ही अधिकारी को समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

(v) यात्रा भत्ते को अनुपात से बांट दिया गया है और अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने दौरे कम करें ताकि प्रत्येक विभाग को आवंटित राशि के भीतर ही व्यय सीमित रहे।

(vi) यह निर्णय किया गया है कि पर्वतीय स्थानों पर सलाहकार-निकायों तथा स्वायत्त संगठनों की बैठकें न की जाएं और रविवार व बन्द छुट्टियों में भी मीटिंग न

की जाए, जिससे समयोपरि भत्ते पर होने वाले खर्च न हों।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से कह दिया गया है कि वे मितव्ययता के नियमों का कठोरता से पालना करें।

शिक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित बजट अनुदानों के व्यय के विभिन्न मदों में 1,53,00,000 रुपए की बचत पर पहले ही प्रभाव पड़ चुका है।

(ख) प्रशासनिक सुधार

(1) मंत्रालय के कार्य को यथोचित आधार पर पुनर्गठित किया गया है और मंत्रालय को 5 सुसंबद्ध विभागों, 5 प्रभागों तथा युनेस्को के एक विशेष एकक में विभाजित किया गया है। पांच विभाग इस प्रकार हैं :—

(i) स्कूल व सामाजिक शिक्षा विभाग।

(ii) उच्च शिक्षा विभाग।

(iii) सांस्कृतिक कार्य कलाप विभाग।

(iv) आयोजन तथा शिक्षा अनुसंधान विभाग ।

(v) छात्रवृत्ति-विभाग।

पाँच प्रभाग ये हैं:—

(i) प्रशासन प्रभाग

(ii) भाषा प्रभाग

(iii) वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा विकास प्रभाग

(iv) शारीरिक शिक्षा प्रभाग,

(v) शैक्षिक समन्वय भाग।

(vi) शिक्षा समन्वय प्रभाग।

2 शिक्षा समन्वय प्रभाग, जो कि पहले पहल स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रयत्नों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा और इसका सम्बन्ध शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने से होगा। यह प्रभाग राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों के संगठन की भी देखभाल करेगा जैसे कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन।

(3) अवमूल्यन के कारण आयात की जाने वाली पुस्तकों की कीमत बहुत बढ़ गयी है और मंत्रालय ने निर्णय किया है कि पुस्तक-विकास कार्य-क्रमों की प्रगति के लिये सभी सम्भव उपाय अपनाए जाएं, जिससे पाठ्य पुस्तक, मानक पुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्री के लिए कालेज व विश्वविद्यालयों की जरूरतें पूरी हो सकें। जिसके जिम्मे यह कार्य होगा, पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग में एक नया प्रभाग बनाया गया है, जो पुस्तक विकास कार्य की विशेषरूप से देख भाल करेगा।

(4) वरिष्ठ पदाधिकारियों को फाइल प्रस्तुत करने के क्रम को पहले से अधिक लचीला बना दिया गया है, जिससे उचित स्तर पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले कम से कम कुछ कम अधिकारियों के पास फाइल जाएगी। इससे कार्य को जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी।

t[THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI M. C. CHAGLA) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The following administrative measures have been taken for expeditious disposal of work in the Ministry and for effecting economy in expenditure:

A. *Economy*

(i) It has been decided not to continue one of the two posts of Secretary in the

t( ] English translation.

Ministry after the present sanction for the post expires on 30th October 1966. The post has not been filled after the present incumbent proceeded 00 leave with effect from 16th August 1966.

(ii) The post of Secretary to Minister which was of the status of Deputy Secretary has been surrendered with effect from 16th August 1966.

(iii) It has been decided that no new administrative post should be created or filled without the specific approval of the Education Minister and that stricter control should be exercised in creating new scientific or technical posts.

(iv) Instructions have been issued that the number of officers attending meetings of Committees etc. should be reduced to the minimum and as far as possible only one officer should represent the Ministry on a Committee.

(v) The travelling allowance provision has been rationed and the officers have been asked to curtail their tours so that the expenditure remains strictly within the amount allocated to each Bureau.

(vi) It has been decided not to hold meetings of Advisory Bodies and autonomous organisations at hill stations and not to hold meetings on Sundays and closed holidays in order to avoid expenditure on over-time allowance.

The University Grants Commission and the Council of Scientific and Industrial Research have been asked to enforce strict economy measures.

A saving of Rs. 1,53,00,000 has already been effected in the various items of expenditure in the Budget Grants with which the Ministry of Education is concerned.

B. *Administrative Reforms*

(1) The work in the Ministry has beer reorganized on a rational basis and the Ministry has been divided into 5 compact Bureaus, 5 Divisions and a Special Unii for Unesco. The 5 Bureaus are—

(i) Bureau of School & Social Edu cation, (ii) Bureau of Higher Education, (iii) Bureau of Cultural Activities.

(iv) Bureau of Planning *h* Educational Research.

(v) Bureau of Scholarships.

The 5 Divisions are—

(i) Administration Division, (ii) Languages Division, (iii) Scientific Surveys and Development Division, (iv) Physical Education Division, (v) Educational Coordination Divir sion.

(2) The Educational Coordination Division which has been set up for the first time will be mainly responsible for the coordination of educational effort at th© national level and will be concerned with the implementation of the recommendations of the Education Commission. This Division will also handle the organisation of national level conferences such as Central Advisory Board of Education and the Education Minister's Conference.

(3) The devaluation has greatly increased the cost of imported books and the Ministry has decided to take all possible measures to promote book development programmes to meet the needs of colleges and universities for text books, standard works and other educational materials. The setting up of a National Book Development Council which will be charged with this work has already been announced. A new Division has been created in the Bureau of Higher Education specially to look after the book development work.

(4) Greater flexibility has been introduced in the submission of files to senior officers and the files will now pass through fewer officers before a final decision is taken at the appropriate level. This will help in the expeditious disposal of work.)

POLITICAL SUFFERERS' REQUEST TO GOVERNMENT

*852. SHRI K. P. MALLIKARJUNU-DU : Will the Minister of HOME AFFATJU be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the last week of July, 1966. some political sufferers met in Delhi and passed resolutions re- I questing Government to grant some »«ri«-